there was a decline in demand for passenger cars, MUL undertook a series of measures including price re-adjustments to stimulate the demand. Due to this, the fourth quarter has seen a growth of 43% over the third quarter in the sales.

राज्यों के औद्योगिक कार्यकरण की समीक्षा

2985. **श्री गोपालसिंह जी0 सोलंकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्यों की औद्योगिक क्षमता और औद्योगिक कार्य-प्रणाली की समीक्षा की हैं ताकि देश के औद्योगिक कार्य-प्रणाली की समीक्षा की हैं ताकि देश के औद्योगिक विकास के प्रतिशत का आकलन किया जा सके,

(ख) यदि हां, तो क्या आकलन के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की प्रतिशतता को निराशाजनक और नकारात्मक पाया गया हैं,

(ग) उसके कारणों सहित ब्यौरा क्या हैं, और

(घ) औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देशभर में सभी राज्यों में फैले हुए औद्योगिक एककों द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्विरणियों के आधार पर तैयार किया जाता हैं । औद्योगिक विकास का मूल्यांकन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता हैं ।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, औद्योगिक विकास अप्रैल-फरवरी, 1997-98 के दौरान 4.9% की तुलना में अप्रैल-फरवरी, 1998-99 के दौरान 3.9% हैं ।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार कार्य निष्पादन के कए विश्लेषण से यह पता चलता हैं कि अप्रैल-फरवरी, 1999 के दौरान कुल 17 द्विअंकीय उद्योग समूहों में से 11 में सकारात्मक विकास दरें प्राप्त हुई हैं जबकि 6 उद्योग समूहों ने नकारात्मक विकास दर्शाया हैं ।

(ग) औद्योगिक विकास में धीमेपन के लिए धरेलू और बाहरी दोनों कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता हैं ।

-घरेलू कारकों में सामान्य निवेश में कमी के कारण कमजोर मांग शामिल हैं, जिसका मुख्य कारण पूंजी बाजार में मंदी की स्थितियां थी ।

-बाहरी पक्ष की दृष्टि से विश्व निर्यात विकास धीमा रहा हैं । जिससे भारत के निर्यात विकास पर प्रभाव पड़ा हैं । चूंकि निर्यात संबंधी उत्पादन औद्योगिक उत्पादन का एक बड़ा भाग होता हैं इसलिए इससे औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा हैं ।

-पूर्वी एशिया और ब्राजील में मुद्राओं के अवमूल्यन के कारण भारतीय कंपनियां सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा की वजह से भी प्रभावित हुई हैं ।

(घ) सरकार ने त्वरित विकास को अधिप्रेरित करने के लिए अनेक उपाय घोष्ज्ञित किये हैं । ये इस प्रकार हैं :-

(1) यू0 एस0 सी0 आर0 ए0 को रद्द करना और गृह स्वामित्व संबंधी प्रोत्साहन ।

(2) सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और पूंजी बाजार को पुनरुजीवित करने के लिए शेयरों की पुनः खरीद व अंतः कारपोरेट ऋणों की अनुमति दी हैं ।

1999-2000 के बजट में, तेजी से औद्योगिक विकास करने के लिए उद्योगों के पुनरुजीवन हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा की गई हैं । जो इस प्रकार हैं :-

(1) एकाधिकार तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम को बदलने के लिए नये प्रतियोगी कानून ।

(2) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन की सूची को बढ़ाया जायेगा ताकि महत्वपूर्ण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकें ।

(3) उद्योग मंत्रालय के भीतर ही एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण गठित करने के घोषणा की गई हैं ताकि निवेश अंतः-प्रवाह में तेजी और परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो सके ।

(4) उत्पादन शुल्क दर में आमूल-चूल परिवर्तन मौजूदा 11 दरों को घटाकर केवल 3 दरें तक दिया गया हैं ।

(5) 100% मोडवेट ऋण को बनाये रखना ।

(6) सीमा शुल्क की मुल्यानुसार 7 प्रमुख दरों को घटाकर 5 मूल दरें की गई हैं ।

(7) सड़क निर्माण पर विशेष जोर जिसके लिए डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त प्रभार के रूप में वित्त सहातया दी गई हैं ।

(8) लघु औद्योगिक इकाइयो के लिए ऋण बीमा योजना चलाई जानी हैं ।

(9) गृह निर्माण क्षेत्र के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा की गई हैं । गृह निर्माण में तेजी से सीमेंट इमारत और अन्दर निर्माण सामक्री की मांग में वृद्धि होगी ।

बजट के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने निधियों की ब्याज लागत घटाने के लिए बैंक दर कम कर दी हैं, "रिपो" दर घटा दी हैं और सीआरआर कम कर दिया हैं ।

Impact of freight hike on Industrial Units

2986. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether recent hike in freight will affect a large number of Industrial Units and consumable items;

(b) if so, the names of such Industrial Units and consumable items separately;

(c) whether Government propose to provide some relief to consumers in view of unconsiderable hike in freight;

(d) if so, the details thereof; a,nd

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRl SIKANDER BAKHT): (a) and (b) It is too early to ascertain the impact of the recent freight increase, as it took effect only from 1.4.1999. Whether it will affect the price of the product will depend upon the market conditions. In conditions of over supply, the increase could be partly or fully absorbed by the producers.

(c) to (e) No such proposal is under consideration.

Allocation under PMRY to Maharashtra

2987. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the district-wise grants allocated to Maharashtra under Prime Minister Rozgar Yojana;

(b) whether any special consideration has been given in allotting such grants in Maharashtra to Adivasi areas;

(c) if so, the number of youths benefitted, district-wise in Maharashtra; and

(d) the steps being taken by Government to increase the mobilisation of funds to Maharashtra?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Under the Prime Minister's Rozgar Yojana, States/UTs are allocated physical targets. The States then allocate district-wise targets. Government of India released funds to States/UTs depending on the achievements of allocated targets only for training purposes and contingencies. The States then incur expenditures for the above purposes.

Subsidy under the scheme is passed on to the Reserve Bank of India for onward disbursement to implementing banks. The statement showing the district-wise allocation of funds under contingencies for the last three years in Maharashtra under the Prime Minister's Rozgar Yojana, as reported by the State Government, is at Statement-I *(See* below). Training funds are not distributed district-wise, but monitored at the State level.

(b) As per report of the State Government, no special consideration has been made while allocating targets/grants to Adivasi areas in Maharashtra.

(c) Details showing district-wise physical targets and progress for the last three years i.e., 1995-96, 1996-97 and